



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 22, 1990/माघ 2, 1911

No. 35] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 22, 1990/MAGHA 2, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या ही आती है जिससे इक यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

समपूर्ण सम्पत्ति अपील अधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1990

का. आ. 70(ब)--- समपूर्ण सम्पत्ति अपील अधिकरण, स्वापक
प्राधिकरण और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61)
की धारा 68ण की उपधारा (5) द्वारा प्रबल शक्तियों का प्रयोग करते
हुए, सिम्लिलित नियम बनाता है, अर्थात् ---

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम
समपूर्ण सम्पत्ति अपील अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ--- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपे-
क्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से स्वापक भ्रोप्रधि और मन: प्रभावी पदार्थ
अधिनियम, 1985 (1985 का 61) अन्वित है।

(ब) "अपील" से धारा 68ण की उपधारा (1) के अधीन फाइल
की गई कोई अपील अन्वित है,

(ग) "अपीलार्थी" से वह व्यक्ति अन्वित है जो सकाम प्राधिकारी के
किसी आदेश से अवित्त होकर अधिरक्षण को अपील करता है,
और इसके अंतर्गत अपीलार्थी का प्राधिकृत प्रतिनिधि भी है।

(घ) "प्राधिकृत प्रतिनिधि" से निम्नलिखित अन्वित है—

(ज) किसी अपीलार्थी के संबंध में,—

(झ) कोई व्यक्ति जो अपीलार्थी का संबंधी है और जो अपीलार्थी
द्वारा अधिकरण के समक्ष हाजिर होने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत
किया गया है; या

(आ) भारत में किसी सिविल न्यायालय में विधि कार्य करने का
लकड़ार कोई विधि व्यवसायी जिसे अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष
हाजिर होने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया है; या

(इ) कोई लेखापाल जो चारटर्ड एकाउन्टेंट अधिनियम, 1949
(1949 का 38) की धारा 3 के अधीन गठित इंस्टीट्यूट आफ चारटर्ड
एकाउन्टेंट आफ हंडिया का या लागत और संकर्म एकाउन्टेंट अधिनियम,
1959 (1959 का 23) की धारा 3 के अधीन गठित इंस्टीट्यूट आफ

कास्ट एवं धर्मसंघारी एकाउन्डेस्ट द्वारा इंडिया का सदस्य है तथा जिसे धर्मसंघारी द्वारा अधिकरण के समक्ष हाजिर होने के लिए सिखिन में प्राधिकृत किया गया है, या

(ii) किसी समक्ष प्राधिकारी के संबंध में, जो अधिकरण ने समक्ष किसी कार्यवाही में एक पक्षपात्र है।—

(अ) केन्द्रीय सरकार का कोई विधि अधिकारी;

(आ) केन्द्रीय सरकार का सरकारी अधिकारी या स्थार्थी परामर्शी, वह किसी भी नाम से जात हो;

(इ) केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी जिसे केन्द्रीय सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्रतिसूचित किया है;

(ई) कोई विधि व्यवसायी या केन्द्रीय सरकार का अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार या समक्ष प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है;

(उ) कोई विधि व्यवसायी या केन्द्रीय सरकार का अधिकारी जो इस प्रकार अधिसूचित या प्राधिकृत यिसी व्यक्ति की ओर से जारी कर रहा है;

(छ) "न्यायपीठ" से धारा 68ए की उपधारा (3) या (4) के प्रवीन गठित अधिकरण की न्यायपीठ प्रभित्रेत है;

(च) "अध्यक्ष" से अधिकरण का अध्यक्ष प्रभित्रेत है;

(छ) "समक्ष प्राधिकारी" से धारा 68ए की उपधारा (1) में परिचयित समक्ष प्राधिकारी प्रभित्रेत है;

(ज) "विधिक प्रतिनिधि" से वह व्यक्ति प्रभित्रेत है जो मूल व्यक्ति की सम्पदा का विभिन्नता प्रतिनिधित्व करता है, और इसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी है जिसे अधिकरण अपने समक्ष लम्बित कार्यवाहियों में मूल व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते वाला मानता है;

(झ) "सदस्य" से अधिकरण का सदस्य प्रभित्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है;

(झ) किसी अपील के संबंध में "पक्षपात्र" से अपीलार्थी अभित्रेत है और "पक्षपात्र" एवं का अर्थ अपीलार्थी और प्रत्यर्थी लगाया जाएगा;

(ट) "रजिस्ट्रार से अधिकरण का रजिस्ट्रार प्रभित्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा अन्य अधिकारी भी है जिसे अध्यक्ष ने रजिस्ट्रार के कुर्सों का प्रवृत्ति करने के लिए प्राधिकृत किया है;

(ठ) "धारा" से अधिनियम की धारा प्रभित्रेत है;

(इ) "अधिकरण" से धारा 68-ड की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित सम्पूर्ण सम्पत्ति अपील अधिकरण प्रभित्रेत है।

3. अधिकरण की भाषा.— (1) अधिकरण के समक्ष सभी अधिकृत, संघित पक्षपात्रों के शिक्षानुसार, अपेक्षी अध्यक्ष इत्यादि में हो सकते हैं।

(2) अधिकरण के सभी आदेश और अन्य कार्यवाहियाँ, अधिकरण के विकल्पानुसार अपेक्षी या हिन्दी में हो सकते हैं।

4. अधिकरण का भूम्यालय प्रादि.— (1) अधिकरण का भूम्यालय नहीं दिल्ली में होगा।

(2) सभी अपीलों और अर्जियों की सुमित्रा सामान्यतया मुख्यालय पर की जाएगी या अध्यक्ष के विवेकानुभाव गुम्बर्द, मत्रास, कलकत्ता, इताहावाद या किसी अन्य स्थान पर दी जा सकती है।

(3) अधिकरण का कार्यालय ऐसे अवश्यक विनों और अन्य अधिकारण विनों को बन्द रहेगा जिन विनों केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालय अंदर रहते हैं।

5. अपील और अर्जियाँ रजिस्टर कर्त्त्व की प्रक्रिया—

(1) अधिनियम की धारा 68ए, 68-ड वा 68-ड की उपधारा

(1) या धारा 68ड के अधीन आदेश से व्यक्ति कोई व्यक्ति अधिकरण को अपील कर सकता है और अपील का जाफा इन नियमों से उपचरण करना में होता है।

(2) अपील का जापन अपेक्षी या हिन्दी में होगा और उसमें अपील के आधार संक्षेप में और विविल यों वाले के अधीन, किसी तक़ या विवरण के बिना, दिए जाएंगे और ऐसे आधारों को क्रमानुसार संलग्नकात् विद्या जाएगा।

(3) अपील का जापन और अपील चार प्रतिशोध में होगी और अपील के जापन की दिग्गज में उसके माथ उग आदेश का, जिसके विवरण अपील की गई है, और प्रतिशोध होनी जिनमें से एक प्रति ऐसे आदेश को प्रमाणित प्रति या अपीलार्थी पर तामील किया गया आदेश होगी।

(4) उपनियम (1) में यथा निर्दिष्ट, इन नियमों से उपचरण प्रक्रियां में कम से 5 पर दिया गया पना, अपीलार्थी का "रजिस्ट्रीकृत पता" कल्पनागत और जब तक अधिकरण को दिए गए आदेश द्वारा, सम्पर्क रूप से परिवर्तन नहीं कर दिया जाता वह अपील तथा अन्य संवेदित कार्यवाहियों में, जब तक कि अपील का अंतिम रूप से अवधारण नहीं हो जाता और उसके परावत सीन मास की अवधि तक, सभी सूचनाओं, आशेयिकाओं और अन्य संस्कृतान्त्रों की तारीख के प्रयोजन के लिए अपील लार्थी का पता समझा जाएगा।

(5) प्रत्येक अपील में समक्ष प्राधिकारी को, जिसने वह आवेदन पारित किया है, जिसके विवरण अपील की गई है, एक प्रत्यर्थी के रूप में पक्षपात्र बनाया जाएगा।

(6) अपील का जापन अपीलार्थी द्वारा स्वयं या जहां एक से अधिक अपीलार्थी हैं वहां उनमें से किसी एक के द्वारा या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा रजिस्ट्रार के मध्यम से अन्य अधिकारी के मन्त्र या अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा या रजिस्ट्रार को संशोधित रजिस्टर द्वाक से भेजा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण— इस उपनियम में, "प्राधिकृत प्रतिनिधि" पर के अंतर्गत अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने के लिए प्राधिकृत किए गए किसी विधि व्यवसायी या अकाउन्टेंट के विनियोजनाधीन कोई व्यक्ति भी है।

(7) जब अपील का जापन रजिस्टरी द्वाक से भेजा जाता है तब उक्त जापन की अधिकरण के कार्यालय पर पहुँच की तारीख अपील दाखिल करने की तारीख होगी और रजिस्ट्रार अपील के प्रन्तेक जापन पर वह तारीख, पृष्ठांकित करेगा जिसको वह अधिकरण के कार्यालय पर प्रस्तुत किया जाता है या, प्राप्त होता है तथा पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करेगा।

(8) जब अपील अपीलार्थी पर तारील किए गए आदेश की प्राप्ति के 45 दिन की समाप्ति के पश्चात किन्तु भाठ दिन के अपश्वान दाखिल की जाती है तब उसके माथ एक शपथ पत्र में समर्थित आवेदन होगा जिसमें उन स्थियों का अधिकरण द्वारा आदेश दिन के भीतर अपील न दाखिल करने के लिए निर्भर करता है कि ऐनालिस दिन के भीतर अपील न दाखिल करने के लिए उसके पास पर्याप्त होता था।

(9) अधिकरण के समक्ष दाखिल की गई प्रत्येक अर्जी के गाथ जिसके अंतर्गत रोकने की अर्जी भी है कि किन्तु औपचारिक या नेमी प्रकृति की अर्जियाँ नहीं हैं, एक सप्तप्रथम होगा और ऐसे दस्तावेजों की चार प्रतियाँ भी होंगी जिन पर वह अपीलार्थी के समर्थन के लिए निर्भर है।

6. अपीलों को रजिस्टर करने की प्रक्रिया— (1) समक्ष प्राधिकारी के आवेदन की तारील के पैसालाइस दिन के भीतर दाखिल प्रत्येक अपील आवेदन जो इन नियमों से उपचरण प्रक्रिया में हो और अन्यथा नहीं है, इस प्रयोजन के लिए रखी गई वहां में रजिस्टर किया जाएगा यो अपील रजिस्टर कहानागी और रजिस्ट्रार नवाचार अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को संमूचित करेगा।

(2) यदि उपनियम (1) के अधीन दाखिल किया गया अपील ज्ञापन त्रुटिपूर्ण है किन्तु लूटियों गौण या तकनीकी प्रक्रिया की है तो रजिस्ट्रार अपील को अनन्तिम आधार पर रजिस्टर भरेगा और अपीलार्थी को उन लूटियों को उनके समय के भीतर ओ विनिविष्ट किया जाए, दूर करने के लिए अड़गा और ऐसी विनिविष्ट अवधि के भीतर लूटियों दूर कर दिए जाने पर रजिस्ट्रीफरण अनन्तिम नहीं रहेगा और अपील उपनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट रूप से अंजिस्टर की गई समझी जाएगी।

(3) जब अपील का ज्ञापन राक्षम प्राधिकारी के आदेश की नामीत या तारीख ने पैतालांस दिन की गमानि पर किन्तु साठ दिन के भीतर दाखिल किया जाए और वह अवधया मही हो, तथा उसके साथ विलंब को माफ करने के लिए अर्जी दी गई हो, तो उसे इस बात के अधीन रहने द्वारा अनन्तिम रूप से संशोधित और रजिस्टर किया जाएगा कि अधिकरण विलंब को माफ कर देगा। विलंब की माफी के लिए अवेदन की सूचना, प्रत्येक की दूरी जा सकती, और पक्कारों को सुनने के पश्चात यदि यह समाधान हो जाना है कि अपीलार्थी समय पर अपील दाखिल करने में पर्याप्त कारणों से निवारित रहा था तो अधिकरण विलंब को माफ कर देगा। तब रजिस्ट्रीफरण अनन्तिम नहीं रहेगा और अपील का निपटारा इस प्रकार किया जाएगा मानो वह उपनियम (1) के अधीन रजिस्टर की गई थी।

(4) जब अपील का ज्ञापन सभाम प्राधिकारी के आदेश की नामीत के पश्चात पैतालीस दिन की समाप्ति के पश्चात किन्तु साठ दिन की अवधि के भीतर, दाखिल किया जाना है और उसके साथ विलंब को माफ करने की अर्जी नहीं दी जाती है तो रजिस्ट्रार अपील को अनन्तिम रूप से रजिस्टर कर सकता है और अपील की अर्जी प्राप्त होने की दशा में उसका निपटारा इस प्रकार किया जाएगा मानो वह अपील के ज्ञापन के साथ प्राप्त हुई थी और तब अपील का निपटारा उपनियम (3) में विहित रूप से किया जाएगा।

(5) यदि इन निमेत विनिविष्ट अवधि के भीतर लूटियों को दूर नहीं किया जाता है या विलंब को माफी के लिए अर्जी दाखिल नहीं की जाती है तो सामग्री अधिकरण के समझ उसके आदेश के लिए रखा जाएगा।

(6) यदि अपील के ज्ञापन को सार्वभूत विशिष्टियों में लूटि हो तो रजिस्ट्रार उन लूटियों की अपीलार्थी को विनिविष्ट कर सकता है या विशित रूप में उन लूटियों को संसूचित दर सकता है। रजिस्ट्रार से अपील का ज्ञापन प्राप्त हो जाने पर अपीलार्थी उभी प्राप्ति के तीस दिन के भीतर लूटियों को सम्बन्ध रूप में दूर करने के अपील ज्ञापन को पुनः प्रस्तुत कर सकता है या उस दिन में जब अपील का ज्ञापन उसे वापस नहीं लौटाया जाता है और लूटियों वेल संसूचित की जाती है वह स्वयं या कारंसल की माफी रजिस्ट्रार के समझ हाजिर हो सकेगा और उन लूटियों को तीस दिन के भीतर दूर कर सकेगा। सत्याकात प्रस्तुत किया गया अपील का ज्ञापन मही पाए जाने पर रजिस्टर किया जा सकेगा।

(7) जब अपील का ज्ञापन प्रथम लूटियों सभाम प्राधिकारी के अपीलार्थी पर आदेश दी तामील की तारीख से साठ दिन से अधिक के पश्चात काटिय किया गया ग्रीन हो तो अपील रजिस्टर नहीं की जाएगी अपितु रजिस्ट्रार अपीलार्थी से यह हेतुक शिक्षित करने की ओक्सा करेगा कि अपील कालांतर होने के कारण खारिज क्यों नहीं कर दी जाए।

(8) विलंब की माफी का प्रत्येक अवेदन और समय के पश्चात फाइल किया गया प्रत्येक अपील का ज्ञापन अधिक के समझ उसके आदेशों के लिए एक जो जाएगा।

7. अपील के अभिस्ट्रीफरण के प्रकार ग्रनिया।—(1) अपील रजिस्ट्रीकृत हो जाने के पश्चात अपील के ज्ञापन अधीन उपांत्यों की एक

प्रति यथाशीघ्र सभाम प्राधिकारी को या तो रसीदी रजिस्ट्री डाक भेजकर या संवेदनाहक के माध्यम से तामील की जाएगी तथा पक्कारों से सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो अनुशासन को जाए अपना पेपर बुक दाखिल करने की अपेक्षा की जाएगी।

(2) प्रत्येक पक्कार अपनी पेपर बुक की जार प्रतिवां दाखिल करेगा—

(i) जो सुपाठ्य रूप से टाइप की गई या किसी यांकिक साधन से अन्यथा तैयार की गई होगी;

(ii) जिसमें वे सभी दस्तावेज होंगे जिन पर पक्कार सुनवाई के अनुबन्ध में निर्भर रहना चाहता है;

(iii) जिसमें केवल ऐसे दस्तावेजों और ऐसी सामग्री होती जो सभाम प्राधिकारी के समझ निविष्ट या प्रस्तुत का गई हो या जिस पर निर्भर किया गया हो ही;

(iv) जिसमें पृष्ठ नमूनार संस्थानिकत होते; और

(v) जिसमें पूरी विषय सूची या विषय सारणी होती है।

(3) यदि उपनियम (2) में निविष्ट पेपर बुक में कोई दस्तावेज अपेक्षी या हिन्दी से भिन्न किसी भाषा में है तो उसका अपेक्षी या हिन्दी में सही अनुवाद भी जोड़ा जाएगा।

(4) पक्कारों को रसीदी रजिस्ट्री डाक से या संवेदनाहक के माध्यम से सूचना तामील करके अपील की सुनवाई की तारीख और समय सूचित किया जाएगा:

परन्तु यदि पक्कार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि अधिकरण के समझ हाजिर है तो अधिकरण उन्हें अपील की सुनवाई की तारीख और समय मीडिक रूप से सूचित कर सकता है।

(5) साधियों या दस्तावेजों को समझ करने के लिए किसी अर्जी पर यदि आवश्यक हो तो, अन्य पक्कार की सूचना देने के पश्चात सुनवाई की जा सकती है।

(6) अधिकरण द्वारा जारी की जाने वाली प्रत्येक अधिकृता, निवेश पत्र, प्राधिकार पत्र या लिखित सूचना पर रजिस्ट्रार हस्ताक्षर करेगा और वह एकी रजिस्ट्री डाक से या संवेदनाहक के माध्यम से भेजा जाएगा या भेजी जाएगी।

8. अपीलों की संयुक्त सुनवाई और निष्पादन :—अधिकरण जब भी वह ऐसा करता आवश्यक या समीक्षीन समझता है एक या अधिक अपीलों को सुनवाई एक साथ कर सकता है और उसका निपटारा एक ही आदेश द्वारा कर सकता है।

9. अपील के आधार.—अपीलार्थी अधिकरण की इजाजत के बिना ऐसे किसी आधार के समर्थन में जो अपील के कारण ज्ञापन में अधिकारित नहीं है, तो वह तक करेगा और न ही उसे सुना जाएगा, किन्तु अधिकरण, अपील का विनिविष्ट करने में केवल उन आधारों तक स्वयं को सीमित नहीं रखेगा जिन्हें अपील के ज्ञापन में उपलिखित किया गया है या जिनके लिए इस नियम के अधीन अधिकरण की मनुमति प्राप्त की गई है:

परन्तु अधिकरण अपना विनिविष्ट अपील के ज्ञापन में अंगित आधारों से भिन्न किसी ऐसे आधार पर तक नहीं करेगा जब सक कि उस पक्कार को जो उससे प्रभावित हो सकता है, उस आधार पर सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है।

10. स्पष्टाक:—अधिकरण किसी मामले की सुनवाई किसी अन्य तारीख के लिए स्थगित कर सकेगा और पक्कारों या उसको और से हाजिर होने वाले उसके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की मामले की सुनवाई की आगामी तारीख और स्थान में मूर्चित करेगा।

11. अपीलार्थी के अधिकरण के कारण अपील का आरिज किया जाना — यदि सुनवाई के लिए नियत दिन या किसी अन्य दिन जिस को सुनवाई स्वयंपत की गई हो अपीलार्थी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि अपील की सुनवाई के लिए पुकार किए जाने पर हाजिर नहीं होता है तो अधिकरण अधिकरण के कारण अपील को आरिज कर सकता है या उसकी एक पक्षीय सुनवाई के लिए अप्रसर हो सकता है।

परन्तु जहाँ अपील अधिकरण के कारण आरिज की गई हो या उस पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई हो और अपीलार्थी तत्पत्ति हाजिर हो जाता है और अधिकरण का यह समाधान कर देता है कि सुनवाई के लिए पुकार किए जाने के समझ उसके हाजिर न होने के लिए पर्याप्त नहुक या तो अधिकरण प्रत्यर्थी को सूचना देने के पश्चात् आरिजी के आवेदन को या एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त कर सकता है और अपील को उसके मूल संघटक पर पुनः रख सकता है।

12. मृत्यु, विवाहितापन आदि की अपील पर प्रभाव -- (1) अपीलार्थी की मृत्यु या उसके विवाहितापन स्थायनिर्णय किए जाने मात्र के कारण अपील उपर्याप्त नहीं होगी।

(2) अधिकरण भूत अपीलार्थी के विधिक प्रतिनिधि द्वारा इस निमित्त आवेदन किए जाने पर उसे पथकार बना सकता है और अपील में आगे कार्यवाई कर सकता है।

(3) यदि अपीलार्थी की मृत्यु के नजदे दिन के भीतर या ऐसी अविरुद्ध प्रवधि के भीतर जो अधिकरण भूत अपीलार्थी के विधिक प्रतिनिधि को अपिलेक पर लाने के लिए अनुमत करे, कोई आवेदन नहीं किया जाता है तो अपील उपर्याप्त हो जाएगी।

(4) अपीलार्थी के विवाहितापन हो जाने पर अपील लेनदारों के फायदे के लिए समनुदेशिती या रिसीवर द्वारा जारी रखी जा सकेगी तथा यदि समनुदेशिती या रिसीवर अपील को जारी रखने में असफल रहता है तो अधिकरण स्वप्रेरणा से या प्रत्यर्थी के आवेदन पर अपील को आरिज कर सकता है।

13. अधिकरण द्वारा मामले का प्रतिप्रेरण -- (1) अधिकरण, जब भी यह आवश्यक समझे, सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश को अपास्त कर सकता है और मामले को ऐसे निवेशों को ध्यान में रखते हुए यैसे यह दे, पुनः अवधारण के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रतिप्रेरण कर सकता है।

(2) अधिकरण यदि कार्यवाही के किसी अनुक्रम पर आवश्यक समझना है तो, ऐसे विषयों पर, जो वह विनिष्ठिट करे, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट या उसके निष्कर्ष मांग सकता है।

(3) उपर्याप्त (2) के अधीन निष्ठिट किसी ऐसी रिपोर्ट या निष्कर्ष की प्रति पक्षकारों को दी जाएगी और इसके पूर्वे कि अधिकरण अंतिम आदेशों की घोषणा करे उन पर पुनः सुना जाएगा।

14. अधिकरण के समझ अंतिरिक्त साक्ष प्रस्तुत करना -- (1) अपील के पथकार, अधिकरण के समझ अंतिरिक्त साक्ष, जहाँ वह मीडिक हो या इस्तावेजी, प्रस्तुत करने के एकादार नहीं होगे किन्तु निम्नलिखित दस्तावेजों में अधिकरण ऐसा साक्ष या दस्तावेज प्रस्तुत करने या साक्षियों की परीक्षा करने की अनुमति दे सकता है, अर्थात् --

(क) जहाँ सक्षम प्राधिकारी ने, जिसके आदेश के विश्वद अपील वालिल की गई है, किसी ऐसे साक्ष को ग्रहण करने से इकार कर दिया हो जो ग्रहण किया जाना चाहिए, या

(ख) जहाँ अंतिरिक्त साक्ष प्रस्तुत करने की प्रारंभना करने याना पथकार यह सिद्ध कर देता है कि सम्यक तत्परता बरते जाने पर भी ऐसा साक्ष उनकी जाकारी में नहीं था या, सम्यक तत्परता बरते जाने के पश्चात् भी वह उस समय 'उनके

द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था जब वह आदेश पारित किया गया या जिसके विश्वद अपील की गई है, या

(ग) जब अधिकरण उसे आदेश विभिन्न करने में समर्थ बनाने के लिए या किसी अन्य नात्तिक कारण से, कोई उस्तावेज प्रस्तुत करने या किसी साक्षी का परीक्षण करने की अपेक्षा किरता है,

(घ) जब अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि सक्षम प्राधिकारी ने मामले का विनिष्ठय अपीलार्थी को उस विषय पर साक्ष प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किए जिता किया है।

(2) अधिकरण जहाँ भी अंतिरिक्त साक्ष प्रस्तुत करने का अनुज्ञा देता है वहाँ वह उसे ग्रहण करने के कारणों को लेखदृढ़ करेगा।

15. अपील की सुनवाई — अपीलों की सुनवाई के प्रयोजनों के लिए अधिकरण की बैठक का स्थान खुला व्यापारस्थ समझा जाएगा जहाँ साधारणता जाता है कि पूर्व वहाँ तक ही सकेगी जहाँ तक वहा उनके लिए सविधाजनक स्थान है:

परन्तु अधिकरण, यदि वह ठंडक समझता है तो, अपील की सुनवाई के किसी अनुक्रम पर यह आदेश कर सकता है कि साधारणतया जाता, या कोई अक्षित विशेष, अधिकरण द्वारा उपयोग किए जा रहे कथ या भवन में नहीं आएगा या वहाँ नहीं रहेगा या रुकेगा।

16. आदेश का सुनाया जाना — सुनवाई की समाप्ति पर अधिकरण तुरंत अपना आदेश सुना सकेगा या अपने आदेश आरक्षित रखे सकेगा और यदि आदेश आरक्षित रखे जाते हैं तो अधिकरण अंतिम आदेश सनाने के पूर्व किसी भी समय या तो स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार के आवेदन पर यह आदेश कर सकेगा कि अपील या अर्जी की पूनः सुनवाई वी जाए।

17. आदेश का पक्षकारों को संमूचित किया जाना — अधिकरण का प्रत्येक आदेश लिखित में होगा और अधिकरण के प्रत्येक अंतिम आदेश की प्रति, जो रजिस्ट्रार द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित की गई हो, पक्षकारों को, यथायंभव भीत्र, निश्चल ही जाएगी।

18. आदेशों पर हस्ताक्षर :— (1) यदि विनिष्ठय पर अधिकरण के भीम सदस्य सहमत हों तो अधिकरण के भीम सदस्यों द्वारा एक ही आदेश पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(2) जो सदस्य बहुमत के विनिष्ठय में सहमत नहीं है वह अहमति का आवेदन पूर्यक दे सकेगा।

(3) जहाँ राय भिन्न हो, वहा विनिष्ठय अधिकरण के सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा।

(4) बहुमत का विनिष्ठय लिखित रूप में दिया जाएगा और उस पर सभी सदस्यों द्वारा, जिनमें असहमत सदस्य भी है, हस्ताक्षर किए जाएंगे।

19. आदेशों का प्रकाशन—अधिकरण के ऐसे आदेश जिन्हें किसी प्राधिकृत रिपोर्ट या समाचारपत्रों में प्रकाशित करने के लिए उपयुक्त समझा जाता है, ऐसे प्रकाशन के लिए, ऐसे निवेशों और शर्तों पर जो अधिकरण अधिकृति करे, दिए जा सकेंगे।

20. कतिपय मामलों में आदेश और निरेश — इन नियमों में किसी बात के हीते हुए भी अधिकरण अपने आदेशों को प्रभावी करने के लिए या अपनी आदेशिकायों का दुरुप्योग निर्धारित करने के लिए या चाथ के उत्तेजों की सुनिश्चित करने के लिए ऐसे आदेश या निरेश के माने जायेंगे वह आवश्यक या समीर्चित मरम्में।

प्रस्तुप

[नियम 5 और 6 वैदिक]

सम्पहुत सम्भानि प्रवीन अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष
अपील क, ज्ञापन

स्वापक श्रीविद्या और मन : प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का संख्या 61) की धारा 68 अ (1)

19 का सं. न. अ. सं./प्र. अ. गं.

(अपील अधिकरण के कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

थो/अंतर्वारी —

अपीलार्थी

बनाम

(i) सधम प्राधिकारी, नई दिल्ली/बम्बई/कलकत्ता/मद्रास/इलाहाबाद

...प्रत्यर्थी

(i) अन्य प्रत्यर्थी, यदि कोई है

गठम प्राधिकारी, नई दिल्ली/बम्बई/कलकत्ता/मद्रास/इलाहाबाद

1. बहु प्राधिकारी जिसके अंदेण के विस्तृ अपील की गई है।

2. आदेश की तारीख

3. आदेश की तारीख की तारीख

4. विनिविष्ट करें कि सुनवाई अविक्षित रूप में आँचित है या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से

5. अपीलार्थी का रजिस्ट्रीकृत पता (जिसके अन्तर्गत फोन में, यदि कोई है) जिस पर ममी
सूचनाएँ, आधेशिकाएँ और संसूचनाएँ तामील भी जाएगी।

6. प्रत्यर्थी का पता

(i) मधम प्राधिकारी नई दिल्ली/बम्बई/कलकत्ता/मद्रास/इलाहाबाद
वाल।

(ii) अन्य प्रत्यर्थी यदि कोई है

7. स्वापक श्रीविद्या और मन : प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की वह धारा या धोरा की
उपचारा जिसके अंतर्गत सधम प्राधिकारी ने आदेश किया है और जिसके विस्तृ अपील
की गई है।

8. दावाकृत अनुमोदन :

(i) क्या पूरा आदेश विवादग्रस्त है:

(ii) यदि गम्भीर कांक्षय के बिल कुछ मद्देन विवादग्रस्त है तो उन्हें उपायवर्त्र में दीर्जिए।

9. अपील के आधार (यदि स्थान पर्याप्त नहीं है तो पृष्ठक पृष्ठ समाइये)

हस्ताक्षर अपीलार्थी

(हस्ताक्षर प्राधिकृत प्रतिनिधि
यदि कोई है)

गत्योपति

क्षमा : अपीलार्थी/अपीलार्थी का प्राधिकृत प्रतिनिधि घोषित करता हूँ कि उपर जो कुछ कहा गया है वह मेरी सर्वानुसन्धानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

आज तारीख : को सत्यापित किया।

स्थान : (अपीलार्थी या उपरोक्त प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)

तारीख :

*जो लागू न होता हो उसको काट दीजिए।

टिप्पण :

- अपील का ज्ञापन चार प्रतियों में द्वायित किया जाना चाहिए औ उसके साथ उस अपील की, जिसके विस्तृ अपील की गई है, चार प्रतियों द्वायित (जिनमें से एक उस आदेश की, जिसके विस्तृ अपील की गई है, अपीलार्थी पर तामील की गई मत्र प्रति या उभरी प्रमाणित छति होगी)। ममी संग्रहक सी चार प्रतियों में होती है।

- 2 अपील का ज्ञापन अपेजी वा हिन्दी में लिखा जाना चाहिए और उसमें प्रपोव के प्राधिकरण संभिल शीर्षों के अधीन शिए जाने चाहिए तथा उसमें कोई तर्क या विवरण नहीं दिये जाने चाहिए और ऐसे आधारों को क्रमानुसार संख्यांकित किया जाना चाहिए।
- 3 यदि प्रपोव के ज्ञापन पर अपीलार्थी द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर कर दिये जाते हैं तो वह पर्याप्त होगा। जहाँ हन पर प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, वहाँ इसके साथ अपीलार्थी का उमके पश्च में प्राधिकार पत्र होगा।
- 4 अन्य व्यांकों के लिए कृपया स्वाक्षर शोषण और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 68 ण की उपधारा (5) के अधीन प्रधिमूचित समाहन सम्मिलित अपील प्रधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 वेदें।

[का. सं. 8 (1)/ए.टी.ए.प. 90]

सम्पन्न सम्भिल अधीन यात्रागत २०११
जी, आर, पटबर्धन, सदस्य

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
APPELLATE TRIBUNAL FOR FORFEITED
PROPERTY
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 1990

S.O. 70(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 68 O of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Appellate Tribunal for Forfeited Property hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Procedure) Rules, 1989.
- (2) They shall come into force at once.
2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires—
 - (a) “Act” means the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 (61 of 1985);
 - (b) “appeal” means an appeal filed under sub-section (1) of section 68 O;
 - (c) “appellant” means a person who, being aggrieved by an order made by the competent authority, prefers an appeal to the Tribunal, and includes the authorised representative of the appellant;
 - (d) “authorised representative” means—
 - (i) in relation to an appellant,
 - (A) any person being a relative of the appellant and authorised in writing by the appellant to attend before the Tribunal; or
 - (B) a legal practitioner entitled to practise in any civil court in India, who is authorised in writing by the appellant to attend before the Tribunal; or
 - (C) an accountant, being a member of the Institute of Chartered Accountants of India constituted under section 3 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38

of 1949) or the Institute of Cost and Works Accountants of India constituted under section 3 of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959), who is authorised in writing by the appellant to attend before the Tribunal, or

- (ii) in relation to a competent authority who is a party to any proceedings before the Tribunal
 - (A) a Law Officer of the Central Government;
 - (B) a Government Pleader or Standing Counsel to the Central Government by whatever name called;
 - (C) any Officer of the Central Government notified in this behalf by the Central Government by notification in the Official Gazette;
 - (D) any legal practitioner or Officer of the Central Government authorised in this behalf by the Central Government or the competent authority;
 - (E) any other legal practitioner or Officer of the Central Government acting on behalf of the person so notified or authorised;
 - (f) “Bench” means a Bench of the Tribunal constituted under sub-section (3) or (4) of section 68 O;
 - (g) “Chairman” means the Chairman of the Tribunal;
 - (h) “competent authority” means a competent authority as defined in sub-section (1) of section 68D;
 - (i) “Legal representative” means a person who in law represents the estate of a deceased person, and includes any person treated by the Tribunal as representing the deceased person in the proceedings pending before the Tribunal;
 - (j) “member” means a member of the Tribunal and includes the Chairman;

- (i) "party" in relation to an appeal means an appellant or the respondent, and the expression "parties" shall be construed to mean the appellant and the respondent;
- (k) "registrar" means the registrar of the Tribunal and includes such other officer who is authorised by the Chairman to perform the functions of the registrar;
- (l) "section" means a section of the Act;
- (m) "Tribunal" means the Appellate Tribunal for Forfeited Property, constituted by the Central Government under sub-section (1) of sec. 68N.

3. Language of the Tribunal—(1) The pleadings before the Tribunal may, at the option of the respective parties, be in English or in Hindi.

(2) All orders and other proceedings of the Tribunal may, at the option of the Tribunal, be in English or in Hindi.

4. Headquarters of the Tribunal, etc. (1)—The Headquarters of the Tribunal shall be at New Delhi.

(2) Appeals and petitions may be heard at the Headquarters or at the discretion of the Chairman, at Bombay, Madras, Calcutta, Allahabad or any other place.

(3) The office of the Tribunal shall observe such public and other holidays as are observed by the offices of the Central Government.

5. Procedure for filing appeals and petitions.—

- (1) Any person aggrieved by an order of the competent authority made under section 68F, section 68I, sub-section (1) of section 68K or section 68L may prefer an appeal to the Tribunal; and every memorandum of appeal shall be in the form annexed to these rules.
- (2) A memorandum of appeal shall be in English or in Hindi and shall set forth concisely and under distinct heads the grounds of appeal without any argument or narrative and such grounds shall be numbered consecutively.
- (3) Every memorandum of appeal or petition shall be in quadruplicate; and in the case of a memorandum of appeal it shall be accompanied by four copies of the order appealed against, one of which shall be either a certified copy of such order or the order served on the appellant.
- (4) The address given at serial number 5 of the form appended to these rules as referred to in sub-rule (1) shall be called the "registered address" of the appellant and shall until duly changed by an application to the Tribunal be deemed to be the address of the appellant for the purpose of the service

of all notices, processes and other communications in the appeal and other connected proceeding, till the final determination of the appeal and a period of three months thereafter.

- (5) In every appeal, the competent authority which passed the order appealed against, shall be impleaded as one of the respondents.
- (6) A memorandum of appeal shall be presented by the appellant in person, or when there are more appellants than one by any of them, or by his authorised representative, to the registrar or such other officer as may be authorised in this behalf by the Chairman, or may be sent by registered post addressed to the registrar.

Explanation.—In this sub-rule, the expression "authorised representative" shall include any person in the employment or a legal practitioner or an accountant who is authorised to appear on behalf of the appellant.

- (7) When a memorandum of appeal is sent by registered post, the date of receipt of the said memorandum at the office of the Tribunal shall be the date of filing of the appeal and the registrar shall on every memorandum of appeal, endorse the date on which it is presented or received at the office of the Tribunal and shall sign the endorsement.
- (8) When an appeal is presented after the expiry of forty-five days of the receipt of the order served upon the appellant but not after sixty days, it shall be accompanied by an application, supported by an affidavit, setting forth the facts on which the appellant relies to satisfy the Tribunal that he had sufficient cause for not preferring the appeal within forty-five days.

- (9) Every petition presented to the Tribunal, including a petition for stay, other than petitions of a formal or routine character, shall be accompanied by an affidavit as also four copies of such documents as are relied upon in support of the petition.

6. Procedure for registration of appeals.—

- (1) Every memorandum of appeal filed within forty-five days of service of the order of the competent authority, being in the form annexed to these rules and otherwise in order, shall be registered in a book kept for the purpose called the Register of Appeals and the registrar shall intimate the appellant or his authorised representative accordingly.
- (2) If a memorandum of appeal filed under sub-rule (1) is defective, but the defects are minor or technical in character, the registrar may register the appeal provisionally and

call upon the appellant to remove the defects within such time as may be specified and upon the defects being removed within such specified time, the registration shall cease to be provisional and the appeal shall be deemed to have been regularly registered under sub-rule (1).

(3) When a memorandum of appeal is presented after the expiry of forty five days but within a period of sixty days, after the date of service of the order of the Competent Authority, and is otherwise in order, and is accompanied by a petition for condonation of delay, it shall be numbered and registered provisionally subject to the delay being condoned by the Tribunal. Notice of the application for condonation of delay may be given to the respondent, and after hearing the parties, the Tribunal may condone the delay on being satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time. The registration of the appeal shall then cease to be provisional and the appeal dealt with as though it has been registered under sub-rule (1).

(4) When the memorandum of appeal is presented after the expiry of forty-five days but within a period of sixty days after the date of service of the order of the competent authority, and is not accompanied by a petition for condonation of delay, the registrar may register the appeal provisionally and call upon the appellant to file a petition for condonation of delay within such time as may be specified and in the event of such a petition being received, it shall be treated as having been received alongwith the memorandum of appeal and the appeal dealt with in the manner prescribed in sub-rule (3).

(5) Where the defects are not removed or a petition for condonation of delay is not filed within the time specified in that behalf, the matter shall be placed before the Tribunal for its orders.

(6) Where a memorandum of appeal is defective in material particulars, the registrar may return the memorandum of appeal specifying the defects to the appellant, or may intimate in writing those defects. On receipt of the memorandum of appeal from the registrar the appellant may within thirty days of its receipt resubmit the memorandum of appeal with defects duly removed or in case of the memorandum of appeal having not been returned to him and defects only having been intimated may appear himself or through Counsel before the registrar and remove those defects within thirty days. The memorandum of appeal submitted thereafter if found in order may be registered.

(7) When a memorandum of appeal on the face of it appears to have been filed more than sixty days after the date of service of the order of the competent authority on the appellant, the appeal shall not be registered but the appellant shall be called upon by the registrar to show cause why the appeal should not be dismissed as being out of time.

(8) Every petition for condonation of delay and every memorandum of appeal filed out of time shall be placed before the Chairman who may direct the petition|appeal to be posted before the Tribunal for its orders.

7. Procedure after registration of appeal :

- (1) After an appeal is registered, one copy of the memorandum of appeal and annexures thereto shall be served, as soon as possible, on the competent authority either by registered post acknowledgement due, or through a messenger and the parties shall be called upon to file their paper-books within a period of thirty days from the date of receipt of the notice or such further time as may be allowed.
- (2) Each party shall file four copies of his paper-book which shall—
 - (i) be legibly typed or otherwise reproduced by mechanical means ;
 - (ii) contain all documents upon which the party proposes to rely during the course of hearing ;
 - (iii) contain only such documents and material as have been referred, produced or relied upon, before the competent authority ;
 - (iv) have pages numbered serially ; and
 - (v) contain a full index or table of contents.
- (3) If the paper-book referred to in sub-rule(2) contain any document in a language other than English or Hindi, a true translation therof in English or Hindi shall be added.
- (4) The parties shall be informed of the date and place of hearing of the appeal either by registered post acknowledgement due or by notice served on them through messenger :
Provided that where the parties or their authorised representatives are present before the Tribunal, it may inform them orally of the date and place of hearing of the appeal.
- (5) Any petition for summoning witnesses or documents filed by a party may be heard, if necessary, after giving notice to the other party.
- (6) Every requisition, direction, letter, authorisation, or written notice to be issued by the Tribunal shall be signed by the registrar and shall be sent by registered post acknowledgement due or through a messenger.

8. Joint hearing and disposal of appeals.—The Tribunal may, whenever it considers necessary or expedient to do so, hear one or more appeals together and dispose of them by a common order.

9. Grounds which may be taken in appeal.—The appellant shall not except with the leave of the Tribunal urge or be heard in support of, any ground not set forth in the memorandum of appeal but the Tribunal, in deciding the appeal, shall not be confined to the grounds set forth in the memorandum of appeal or taken with the leave of the Tribunal under this rule :

Provided that the Tribunal shall not rest its decision on any ground other than the grounds set forth in the memorandum of appeal unless the party which may be affected thereby has had a reasonable opportunity of being heard on that ground.

10. Adjournment.—The Tribunal may adjourn the hearing of any case to any other date and inform the parties or their authorised representatives appearing on their behalf of the next date and place of hearing of the case.

11. Dismissal of appeal for appellant's default.—Where on the day fixed for hearing or on any other day to which the hearing may be adjourned, the appellant or his authorised representative does not appear when the appeal is called on for hearing, the Tribunal may either dismiss the appeal for default proceed ex parte.

Provided that where the appeal has been dismissed for default or proceeded with ex parte and the appellant appears thereafter and satisfies the Tribunal that there was sufficient cause for his non-appearance when the appeal was called on for hearing, the Tribunal shall, after giving notice to the respondent, make an order setting aside the dismissal order or the ex parte proceedings and restoring the appeal to its original number.

12. Effect of death, insolvency, etc. on appeal.—(1) An appeal shall not abate by reason only of the death of an appellant or on his adjudication as an insolvent.

(2) The Tribunal may on an application made in this behalf by a legal representative of a deceased appellant make him a party and proceed with the appeal.

(3) When no application is made within ninety days of the death of an appellant or within such further time as the Tribunal may allow for bringing his legal representative on record, the appeal shall abate.

(4) On the insolvency of an appellant, the appeal may be continued by the assignee or the receiver for the benefit of creditors and if the assignee or the receiver fails to continue the appeal, the Tribunal may on its own motion or on an application by the respondent, dismiss the appeal.

13. Remand of case by the Tribunal.—(1) The Tribunal may, whenever it considers it necessary, set aside an order of the competent authority and remand

the case to the competent authority for fresh determination in the light of such directions as it may give.

(2) The Tribunal may if it considers necessary at any stage of the proceedings call for a report or finding from the competent authority on such matters as it may specify.

(3) A copy of any such report or finding referred to under sub-rule (2) shall be furnished to the parties and they shall be heard thereon before the Tribunal pronounces final orders.

14. Production of additional evidence before the Tribunal.—(1) The parties to an appeal shall not be entitled to produce additional evidence, whether oral or documentary, before the Tribunal, where—

- (a) the competent authority from whose order the appeal is preferred has refused to admit evidence which ought to have been admitted, or
- (b) the party seeking to produce additional evidence, establishes that notwithstanding the exercise of due diligence, such evidence was not within his knowledge or could not, after the exercise of due diligence, be produced by him at the time when the order appealed against was passed, or
- (c) the Tribunal requires any document to be produced or any witnesses to be examined to enable it to pronounce orders, or for any other substantial cause, or
- (d) the Tribunal is satisfied that the competent authority has decided the case without giving a reasonable opportunity to the appellant to adduce evidence on any point.

it may allow such evidence or document to be produced, or witness to be examined.

(2) Wherever additional evidence is allowed to be produced by the Tribunal, it shall record the reason for its admission.

15. Hearing of appeals.—The place in which the Tribunal sits for the purpose of hearing appeals shall be deemed to be an open court, to which the public generally may have access so far as the same can conveniently contain them :

Provided that the Tribunal may, if it thinks fit, order at any stage of the hearing of an appeal, that the public generally, or any particular person, shall not have access to, or be or remain in, the room or building used by the Tribunal.

16. Pronouncement of order.—After the hearing is over, the Tribunal may pronounce its order forthwith, or it may reserve its order and if the orders are reserved, the Tribunal may at any time before final orders are pronounced either on its own motion or on the application of a party or that the appeal or petition be re-heard.

17. Order to be communicated to parties.—Every order of the Tribunal shall be in writing and a copy of every final order of the Tribunal certified as a true copy by the registrar shall be supplied free of cost to the parties as early as possible.

18. Signing of orders.—(1) Where the decision of the Tribunal is unanimous, a common order shall be signed by all the Members of the Tribunal.

(2) A Member who does not concur with the decision of the majority may deliver a dissenting order.

(3) Where there is a difference of opinion, the decision shall be in accordance with the decision of the majority of Members of the Tribunal.

(4) The decision of the majority shall be reduced to writing and signed by all the members including the dissenting member.

19. Publication of orders.—Such of the orders of the Tribunal as are deemed fit for publication in any authoritative report or the press may be released for such publication on such terms and conditions as the Tribunal may lay down.

20. Orders and directions in certain cases.—Notwithstanding anything contained in these rules, the Tribunal may make such orders or give such directions as may be necessary or expedient to give effect to its orders or to prevent abuse of its process or to secure the ends of justice.

FORM

(See rules 5 and 6)

BEFORE THE APPELLATE TRIBUNAL FOR FORFEITED PROPERTY, NEW DELHI. MEMORANDUM OF APPEAL

Section 68-O(1) of the Narcotic Drugs & Psychotropic Substances Act, 1985 (Act No. 61 of 1985)

F.P.A. No. M.P. No. _____ of ____ 19_____
To be filled up by the office of the Appellate
Tribunal.

IN THE MATTER OF

Shri/Smt. _____ ... APPELLANT.

VS.

(i) The Competent Authority, New Delhi
Bombay|Calcutta|Madras>Allahabad

... RESPONDENT

(ii) Other respondents, if any _____

1. Authority passing the order
appealed against.

Competent
Authority,
New Delhi*

Bombay|
Calcutta|Madras|
Allahabad.

2. Date of the order.
3. Date of service of the order.
4. Specify whether a hearing in person or through an authorised representative is desired.
5. Registered address of the appellant (including telephone No., if any for the service of all notices, processes and communications).
6. Address of the Respondent.
 - (i) The Competent Authority, New Delhi
Bombay|Calcutta|
Madras>Allahabad.
 - (ii) Other respondents, if any.
7. Section or sub-section of the section of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 under which the Competent Authority passed the order and which is appealed against :
8. Relief claimed :
 - (i) Specify whether the entire order is disputed :
 - (ii) If only certain items of properties are disputed, enumerate them in an annexure :
9. Ground of appeal (Annex a separate sheet if space is not sufficient) :

(Signature of Appellant)

Signature of Authorised Representative, if any.

VERIFICATION

I, _____ the appellant|authorised representative of the appellant, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge, information and belief. Verified today the _____ day of _____, 19 _____.

Place : _____

Date : _____

(Signature of the appellant
or his authorised
representative)

* Strike out whatever is inapplicable.

Notes :

1. The memorandum of appeal should be filed in quadruplicate accompanied by four copies of orders appealed against (one of which shall be a certified copy of the order appealed against or the original copy of it served on the appellant). Any enclosures will also be in quadruplicate.
2. The memorandum of appeal should be written in English or in Hindi and should set forth concisely and under distinct heads the grounds of appeal and should be without any argument or narrative and such grounds should be numbered consecutively.
3. It is enough if the memorandum of appeal is signed either by the appellant or the authorised representative. Where it is signed by the authorised representative, it should be accompanied by an authorisation of the appellant in his favour.
4. For further details see the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Procedure) Rules, 1989 notified under sub-section (5) of section 68 O of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.

[F. No. 8(1)ATFP|90]

By Order of the Appellate
Tribunal for Forfeited Property.
G. R. PATWARDHAN, Member

